आवें शहादत दिवस को शपथ लें, ऑपरेशन ग्रीन हंट को परास्त कर जारी जनयुद्ध को और एक कदम आगे बढ़ाएं!

प्रिय कामरेडो एवं जंग-ए-अवामी,

पार्टी शहादत दिवस के अवसर पर सर्वप्रथम इआरबी हमारी पार्टी भाकपा (माओवादी) के संस्थापक, शिक्षक और भारतीय क्रांति के महान नेता कामरेड चारू मजुमदार और कामरेड कन्हाई चटर्जी को शत्-शत् लाल सलाम पेश करती है। साथ ही साथ उन तमाम वीरों और वीरांगनाओं को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करती है, जिनकी शहादत के बदौलत क्रांतिकारी संघर्ष को जनयुद्ध के इस मुकाम तक पहुंचाने में हम कामयाब हुए हैं। नक्सलबाड़ी सशस्त्र कृषि क्रांतिकारी संघर्ष से लेकर अबतक लगभग 15-16 हजार और भारत की कम्युनिस्ट पार्टी गठन होने से अबतक 3 हजार से अधिक वीरों और वीरांगनाओं ने शहादत दी है और विगत एक वर्ष में पूरे इआरबी क्षेत्र के अन्तर्गत 26 वीरों और वीरांगनाओं ने अपनी जान को निछावर किया है। उन अमर शहीदों में केन्द्रीय कमिटी व पोलित ब्यूरो सदस्य कामरेड नारायण सन्याल उर्फ विजय दा, जिनकी शहादत 17 अप्रैल, 2017 को कैंसर की बीमारी से हुई, केन्द्रीय कमिटी के और एक सदस्य कामरेड कुप्पु देवराज उर्फ योगेश जिनको दुश्मनों ने फर्जी मुठभेड़ में 24 नवम्बर, 2016 को हत्या की और उनके साथ ही एसजेडसी सदस्या कामरेड अजिता की भी हत्या की और वे शहीद हुए; बीजे सैक सदस्य कामरेड आशीष को 11 सितम्बर, 2016 को कोवर्ट की सूचना पर पुलिस ने घातलगाकर हमला करके घायल अवस्था में पकड़ कर यातना देकर मार दिया और वे शहीद हुए, पश्चिम बंग राज्य कमिटी के पूर्व सचिव कामरेड हिमाद्री सेन उर्फ विधान दा बीमारी से 3 अगस्त, 2016 को शहीद हुए, राज्य स्तरीय वरिष्ठ कामरेड रघुनाथ महतो उर्फ मुर्मू जी 93 वर्ष की उम्र में 26 अक्टूबर, 2016 को शहीद हुए। इअरबी के अन्तर्ग शहीद हुए 26 कामरेडों में से सैक/राज्य सदस्य 3, रीजनल सदस्य 1, जोनल सदस्य 4, सबजोनल सदस्य 5, एरिया कमिटी सदस्य 4, पीएल सदस्य 2, एलजीएस सैनिक 3, केकेसी सदस्य 2 और समर्थक 1 शामिल हैं। आवें, शहादत दिवस के अवसर पर हम उन तमाम वीर शहीदों के अधूरे सपना को साकार करने हेतु क्रांतिकारी संघर्ष को और एक कदम आगे बढ़ाने की शपथ लें।

प्रतिक्रांतिकारी युद्ध से लोहा लेता क्रांतिकारी जनयुद्ध

दोस्तो, ज्यों-ज्यों क्रांतिकारी संघर्ष आगे बढ़ रहा है त्यों-त्यों वर्ग दुश्मनों का दमन अभियान भी और तीखा होता जा रहा है। परिणामस्वरूप शहादतों की संख्या में भी बढ़ोतरी हो रही है। जिससे हसिया-हथौड़ा अंकित लाल झण्डा और सुर्ख होकर क्रांति के

पथ को आलोकित कर रहा है। भारतीय क्रांतिकारी संघर्ष आगे बढ़ता हुआ युद्ध का रूप ले चुका है। यह जारी जनयुद्ध अब वर्ग दुश्मनों के लिए चुनौती बन गया है। इसको कुचल डालने के बुरे इरादे से साम्राज्यवाद के दलाल भारतीय शासक वर्ग- सामंती जमीन्दार और दलाल नौकरशाह पूंजीपति वर्ग व उनके प्रतिनिधित्वकारी राजनीतिक पार्टियां कांग्रेस और भाजपा नेतृत्वाधीन यूपीए और एनडीए की सरकार ऑपरेशन ग्रीन हंट नामक प्रतिक्रांतिकारी युद्ध जनता के माथे थोप दिया है, जिसका तृतीय चरण चल रहा है। उसका दमनात्मक अभियान और क्रूर होता जा रहा है। जिसके तहत भाकपा (माओवादी) के नेताओं, कार्यकर्ताओं और समर्थक जनता पर बर्बर हमले, फर्जी मुठभेड़ में हत्याएं व नरसंहार करना, फर्जी मुकदमा में सालों दर साल, एक के बाद एक केस लादकर जेल में कैद करके रखना, कुर्की-जब्ती के नाम पर जनता की संपदा की लूटपाट करना, घरों में आग लगाना, ढाहना, मां-बहनों का बलात्कार करना आदि चलाया जा रहा है।

दूसरी तरफ हमारी पार्टी भाकपा (माओवादी) के नेतृत्व में जनता के जनफौज- जन मुक्ति छापामार सेना (पीएलजीए) पुलिस व अर्द्धसैनिक बलों के क्रूर हमले का मुकाबला करते हुए क्रांतिकारी संघर्ष को आगे बढ़ाते जा रही है। हां, अवश्य ही हमारा क्रांतिकारी आन्दोलन एक कठिन दौर से गुजर रहा है। फिलहाल वर्ग दुश्मन के हाथ में जहां अत्याधुनिक हथियारों, इंसास, एके-47, 56, इजराइली टावोरेक्स-95, एलएमजी, मोर्टार, रॉकेट लांचर आदि और अत्याधुनिक उपकरणों- जीपीएस, सेटेलाइट फोन, यूएवी, ड्रोन, माइनप्रुफ-बुलेटप्रुफ वाहन, बुलेटप्रुफ जैकेट आदि से लैस विशाल संख्यक अर्द्ध सैनिक बल हो, और हमारे पास न तो पर्याप्त मात्रा में अत्याधुनिक हथियार है और न हीं कोई अत्याधुनिक उपकरणों से लैस है हमारे पीएलजीए बल तथा संख्यागत रूप से भी दुश्मन के बलों की तुलना में नगन्य रहने के कारण सापेक्षिक रूप से हम कमजोर हैं। इसलिए अभी की परिस्थिति में क्रांतिकारी आन्दोलन का कठिन दौर से गुजरना या मुश्किलों का सामना करना अपरिहार्य वस्तुगत सच्चाई है आत्मगत शक्ति के दृष्टिकोण से। लेकिन यह अस्थाई है। यह परिस्थिति का एक पहलू है।

दूसरा पहलू है, शोषक-शासक वर्ग एकमात्र बन्दूक और पुलिस-फौज के बल पर ही अपने लूट-शोषण पर आधारित शासन व्यवस्था को टिका कर रखा है। तथाकथित लोकतंत्र तो केवल दिखावा या ढोंग है, बन्दूक और फौज के बल पर चलाया जाने वाला शासन-तंत्र राज्यमशीनरी या राष्ट्रयंत्र (लूटेरे कानून, नौकरशाह, पुलिस-फौज और जेलखाना) ही जो असली है, उस पर पर्दा डालता है। वर्तमान यह शासन व्यवस्था मुट्ठीभर सैकड़ा में 10 प्रतिशत लोगों (साम्राज्यवाद, सामंतवाद और दलाल नौकरशाह पूंजीपति वर्ग) का 90 प्रतिशत लोगों (किसान-मजदूर और मेहनतकश वर्ग) पर तानाशाही है। ये 90 प्रतिशत किसान-मजदूर, मेहनतकश जनता हमारे क्रांतिकारी आन्दोलन के पक्ष में हैं लेकिन फिलहाल असंगठित हैं। इसलिए उन मुट्ठीभर 10 प्रतिशत लोगों का शासन व तानाशाही तबतक टिकी रहेगी जबतक किसान-मजदूर, मेहनतकश जनता क्रांतिकारी राजनीति से सचेतन व जागरूक होकर संगठित नहीं हो जाती तथा अपनी हथियारबंद फौज का निर्माण

कर वर्तमान शोषणमूलक सत्ता को उखाड़ फेंकने के हथियारबंद क्रांतिकारी संघर्ष या जनयुद्ध में शामिल नहीं हो जाती।

किसान-मजदूर व मेहनतकश जनता के विरोधी तथा 'देशी'-विदेशी पूंजीपति व कॉरपोरेट घरानों के हित में काम करती मोदी सरकार

केन्द्र में भाजपानीत नरेन्द्र मोदी के सरकार के तीन साल पूरे होने पर भाजपा द्वारा पूरे देश के पैमाने पर खासकर भाजपा शासित राज्यों में बड़े तामझाम के साथ जश्न मनाया गया और अपनी उपलब्धियां गिनाया। और, मुख्य रूप से भाजपा के नेताओं ने यही कहा कि 70 साल में जो विकास नहीं हुआ, नरेन्द्र मोदी उसे तीन साल में करके दिखाया। लेकिन जिन वादे के साथ नरेन्द्र मोदी सरकार सत्ता में आयी, अच्छे दिन आएंगे, सबका साथ सबका विकास, विदेश से काला धन वापस लाने, हर साल दो लाख युवाओं को रोजगार देने आदि का क्या हुआ इस पर किसी ने भी चर्चा नहीं की। वास्तव में देखा जाय तो इस सरकार के दौरान कॉरपोरेट घरानों, व्यापारी व शेयर मार्केट के अच्छे दिन आ गये। सरकार के पास कॉरपोरेट के लाखों करोड़ कर्ज माफी के लिए पैसे हैं, लेकिन किसानों और मजदूरों की भलाई के लिए फंड की कमी है। युवाओं के लिए रोजगार के अवसर नहीं है, किसान आत्महत्या करने पर मजबूर है और मजदूरों के लिए सामाजिक सुरक्षा की गारंटी खत्म हो गई है।

वर्ष 2014 में वादा किया गया था कि सालाना दो लाख युवाओं को रोजगार मुहैया कराया जाएगा, लेकिन रोजगार पैदा करने के उलट आज बेरोजगारी का संकट गंभीर हो गया है। पिछले तीन साल में सरकार की नीतियों के कारण रोजगार के अवसर कम हुए हैं। दरअसल सरकार की मौजूदा आर्थिक नीतियों के केन्द्र में आम लोग की बजाय कंपनियों का हित मायने रखता है। सरकार की नीतियां सिर्फ पूंजीनिवेश को आकर्षित करने पर केन्द्रित है। हमें यह समझना होगा कि पूंजी निवेश बढ़ने से रोजगार के अवसर नहीं बढ़ते हैं। ऊपर से सरकार ने नोटबन्दी का फैसला ले लिया। इसके कारण देश के छोटे-छोटे उद्योग पर ऐसी मार पड़ी कि वह हमेशा के लिए पंगु बन गये। देश में रोजगार मुहैया कराने में छोटे उद्योगों का सबसे अधिक योगदान रहा है। साथ ही सरकारी खर्च में कटौती के नाम पर विभिन्न विभागों में नियुक्तियां पर रोक लगाने से रोजगार के अवसर कम हुए हैं। सरकार सिर्फ आर्थिक विकास को पैमाना मान रही है। लेकिन नव उदारवादी आर्थिक नीतियों के कारण रोजगार के अवसर कम हुए हैं। एक ओर सरकार कहती है कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी कर दी जाएगी। लेकिन किसानों की आय बढ़ाने की बजाय कृषि क्षेत्र को निजी हाथों में सौंपने की तैयारी की जा रही है। नीति आयोग के कृषि बाजार सुधार संबंधी नौ सूत्रीय कार्यक्रम इस ओर इशारा कर रहे हैं। आज किसान दयनीय हालात में है और इस कारण आत्महत्या लगातार बढ़ रही है। बैंक कर्ज देने में आनाकानी करते हैं, लेकिन बड़े व्यापारी कर्ज लेकर भी पैसा नहीं चुकाते हैं। काले ध न के नाम पर नोटबंदी कर दी गयी, लेकिन इस फैसले से समाज के गरीब तबकों पर सबसे प्रतिकूल असर पड़ा। सरकार यह बताने को तैयार नहीं है कि नोटबंदी से कितना

कालाधन आया। देश में भ्रष्टाचार पर लगाम नहीं लग पायी है। खुद प्रधानमंत्री मोदी पर सहारा-बिड़ला डायरी में पैसे लेने का आरोप लगा, ललित मोदी को लाभ पहुंचाने, छत्तीसगढ़ में राशन कार्ड घोटाला, मध्यप्रदेश में व्यापम के गंभीर आरोप लगे। लेकिन इन आरोपों को जवाब देने की बजाय सरकार लोगों का ध्यान हटाने के लिए शिक्षण संस्थानों में दखल, राष्ट्रवाद के मुद्दे को हवा देती रही। मौजूदा माहौल में देश में गरीब, अल्पसंख्यक, दलित, आदिवासी के अधिकार हासिये पर चले गये हैं। निम्न आंकड़े इस सच्चाई को ही प्रमाणित करते हैं जो निम्न प्रकार हैं।

जनवरी-मार्च में जीडीपी ग्रोथ सिर्फ 6.1 प्रतिशत, मैन्युफैक्चरिंग 12.7 प्रतिशत से घटकर 5.3 प्रतिशत रही।

पिछले दो दशकों में कर्ज के बोझ में 3 लाख से अधिक किसान आत्महत्या कर चुके हैं, वहीं पिछले चार साल के अन्दर छत्तीसगढ़ में 1585 और पिछले एक साल में 955 किसानों ने आत्महत्या कर आन्ध्रप्रदेश, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश और तमिलनाडु को पीछे छोड़ दिया है।

बेरोजगारी की दर बेलगाम हो चुकी है। लेबर ब्यूरो के सर्वे के अनुसार बेरोजगारी दर बीते पांच सालों के अधिकतम स्तर पर है। एक स्वयंसेवी संस्था के शोध के नतीजे संकेत कर रहे हैं कि समय रहते नहीं चेता गया, तो स्थिति बेहद गंभीर हो सकती है, क्योंकि बेरोजगारी के मोर्चे पर देश दोहरी मार झेल रहा है। एक तो रोजगार के नये अवसर वांछित तादाद और रफ्तार से पैदा नहीं हो रहे, दूसरे रोजगार के मौजूदा अवसरों में कमी आ रही है। शोध का निष्कर्ष है कि बीते चार सालों में देश से हर दिन औसतन 550 नौकरियां खत्म हुई हैं और यही स्थिति रही तो 2050 तक 70 लाख नौकरियां खत्म हो जाएंगी। विश्व बैंक के ताजा आकलन के मुताबिक उत्पादन और वितरण के अधिकाधिक मशीनीकृत होते जाने के कारण भारत में करीब 69 फीसदी नौकरियां के खत्म होने का खतरा है। लेबर ब्यूरो के आंकड़ा के अनुसार 15 साल या इससे ज्यादा उम्र के मौजूदा कार्यबल में बेरोजगारी दर 5 फीसदी पर पहुंच गयी है और कार्यबल के एक तिहाई (35 फीसदी) हिस्से को साल में कुछ महीने ही रोजगार मिलता है। जनगणना के मुताबिक, देश में 15 साल या इससे ज्यादा उम्र के 45 करोड़ लोग हैं। यानी जीविका तलाशते लगभग 2.3 करोड़ लोग रोजगार के किसी भी अवसर से वंचित हैं और 16 करोड़ के पास पूरे साल चलनेवाला स्थायी रोजगार नहीं है। ध्यान रहे कि देश के श्रमबल का 47 फीसदी हिस्सा स्वरोजगार पर निर्भर है, जहां नियमित आय की गारंटी नहीं है। देश के 68 फीसदी परिवारों की सभी स्रोतों से कुल आय 10 हजार से ज्यादा नहीं हो रही। 77 फीसदी ग्रामीण परिवार महीने में 10 हजार भी नहीं कमा पा रहे।

आइटी सेक्टर में भी बड़ी संख्या में नौकरी जाने की नौबत बन गई है। विप्रो ने अपने 600 कर्मचारियों की छंटनी करने का निर्देश जारी किया है। सर्च इंजन कंपनी हेड हंटर इंडिया के अनुसार अगले तीन साल तक सूचना प्रोद्योगिकी क्षेत्र में सालाना 1.75 लाख

से दो लाख के बीच रोजगार के अवसर में कटौती की जा सकती है।

संयुक्त राष्ट्र संघ की नार्वे शरणार्थी परिषद की रिपोर्ट में विस्थापन की समस्या से सबसे अधिक प्रभावित देशों में भारत का तीसरा स्थान हैं, जहां 2016 में करीब 28 लाख लोग विस्थापित हुए हैं।

कुपोषण के मामले में संयुक्त राष्ट्र का आकलन है कि भारत में प्रतिवर्ष कुपोषण से मरनेवाले पांच साल से कम उम्र के बच्चों की संख्या दस लाख से ज्यादा है। भारत में विश्व की 17.5 प्रतिशत आबादी रहती है, जबकि विश्व की कुल कुपोषित आबादी का 24.5 प्रतिशत भारत में रहती है। अल्प कुपोषित जनसंख्या भारत में काफी ऊंची है। 55.3 प्रतिशत भारतीय महिलाएं कुपोषित हैं।

स्कूल जाने की उम्र वाला हर चार में से एक बच्चा स्कूल से बाहर है, करीब 10 करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर हैं, जिन्हें स्कूलों में होना चाहिए। 100 में से सिर्फ 32 बच्चे स्कूली शिक्षा पूरी कर पाते हैं। देश में केवल दो प्रतिशत स्कूल ऐसे हैं, जो क्लास एक से 12वीं तक की पूरी शिक्षा दे पाने की स्थिति में हैं। बच्चों के स्वास्थ्य के मामले में भारत की हालत सबसे बदतर है। 54 प्रतिशत बच्चे कुपोषित हैं।

ये आंकड़े मोदी सरकार के कामकाज की असलित को दिखाने के लिए पेश किया गया है।

राजनीतिक सत्ता का बढ़ता सैन्यीकरण व फासीवादीकरण

आज भाजपानीत केन्द्र की मोदी सरकार हो या भाजपा शासित राज्य सरकारें हो पूंजीपति और कॉरपोरेट घरानों के लूट-शोषण को बरकरार रखने के लिए पूरे राजमशीनरी का इस्तेमाल कर रही है। नरेन्द्र मोदी विदेशी पूंजीपतियों के लूट को सुगम बनाने के लिए सत्ता में आने के साथ भूमि अधिग्रहण कानून में बदलाव लाया, लेबर कानून में बदलाव लाया, ठीक उसी के तर्ज पर राज्य सरकार खासकर झारखण्ड में रघुवर दास तमाम विपक्षी पार्टियों के जबरदस्त विरोध के बावजूद सीएनटी-एसपीटी एक्ट में बदलाव लाने पर आमादा है। उसी तरह पश्चिम बंग की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी गोरखा राष्ट्रीयता की जनता के आत्मनिर्णय के आन्दोलन को बूटों तले दमन करने पर आमादा है। अलावे पूरे पूर्वोत्तर भारत के राष्ट्रीयता के आत्मनिर्णय के आन्दोलन को दमन करने हेतु मिलिटरी को तैनात करके रखा गया है। कश्मीरी राष्ट्रीयता के आत्मनिर्णय के आन्दोलनकारियों के साथ तो आतंकवादी व बाहरी दुश्मन जैसा सलूक किया जाता है। और कश्मीर तो एक युद्धक्षेत्र में तब्दील हो गया है। पिछले वर्ष सेना द्वारा पैलेटगन क इस्तेमाल 100 से अधिक लोगों की जानें गई और एक हजार से अधिक लागों के आंखों की रोशनी चली गई। इस तरह जोर-जबरन भूमि अधिग्रहण के सवाल पर हो अथवा सीएनटी-एसपीटी में बदलाव लाने के सवाल पर हो या राष्ट्रीयता के आन्दोलन को दमन करने के मामले में हो, या विशेष आर्थिक क्षेत्र (स्पेशल इकोनॉमिक जोन-सेज) और आर्थिक गलियारा (इकॉनोमिक कॉरिडोर) बनाये जाने पर उत्पन्न विस्थापन समस्या के खिलाफ उठाये जाने वाले विरोध

ी स्वर को, सभी बूटों तले रौंदा जा रहा है। झारखण्ड के रामगढ़ गोला व हजारीबाग बड़कागांव, मध्यप्रदेश के मंदसौर, की घटना, दार्जिलिंग में गोरखा राष्ट्रीयसत्ता के आन्दोलन कारियों पर गोली चलाकर हत्या करने और कश्मीरी कजता के ऊपर बर्बर सैन्य कार्रवाई की घटना इसकी जीती-जागती मिसाल है। आज हर प्रशासनिक काम जोर-जबरन पुलिस और फौज के बल पर किया जा रहा है। भाकपा (माओवादी) के नेतृत्व में जल-जंगल-जमीन सहित तमाम संपदा पर जनता का अधिकार कायम करने तथा आर्थिक-राजनीतिक अधिकार कायम करने हेतु जारी क्रांतिकारी आन्दोलन के ग्रामीण क्षेत्रों को तो पुलिस छावनी में तब्दील कर ही दिया गया है। यहां तो कोई भी ऐसा काम नहीं है जो बिना पुलिस व अर्द्ध-सैनिक बलों के जरिए किया जाता हो।

वहीं दूसरी तरफ पूरे सत्ता के संरक्षण में विश्व हिन्दु परिषद व आरएसएस के एजेण्डे को लागू करने के लिए भगवा ब्रिगेड सक्रिय हो गये हैं और उसका आतंक काफी बढ़ गया है। गोरक्षा के नाम पर मुस्लिम अल्पसंख्यकों और दलितों पर कहर बरपाया जा रहा है। फिर, पूरे सुनियोजित साजिश के तहत भीड़ के द्वारा हमले करवाकर अल्पसंख्यकों और दलितों की हत्याएं करवाई जा रही हैं। हरियाणा के बल्लभगढ़, उत्तर प्रदेश के दादरी, सहारनपुर, गुजरात के उना, राजस्थान, दिल्ली और झारखण्ड के पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला-खरसावां, रामगढ़, गिरिडीह की घटना इसकी जीती-जागती मिसालें हैं। इस तरह गीता पर हाथ रखकर संविधान की रक्षा करने की कसम खानेवाले ही आज संविधान (धर्मनिरपेक्षता) की धजियां उड़ा रहे हैं। पूरे देश में सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है और इससे समाज में असहिष्णुता बढ़ रही है।

दुश्मन द्वारा एलआईसी पॉलिसी के तहत क्रांतिकारी आन्दोलन पर किये जा रहे चौतरफा हमले को पहचानें तथा उसे परास्त करने हेतु पार्टी और फौज को बोल्शेवीकीकरण करने के अभियान को तेज करें

वर्ग दुश्मन हमारे क्रांतिकारी आन्दोलन को कुचलने के बुरे मनसूबे से एलआईसी पॉलिसी के तहत चौतरफा हमले चला रहा है। इसके तहत जहां एक ओर क्रूर व बर्बर सैन्य दमन अभियान चलाया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ पार्टी के अन्दर कोवर्ट (भीतरघाती) घुसाकर हमले करवाना, गुटबाजी पैदा करके आपस में फूट डालना व गुटीय संघर्ष में फंसाकर आत्मगत शक्ति को कमजोर करना और क्रांतिकारी आन्दोलन से गुमराह करने के लिए आत्मसमर्पण पॉलिसी के तहत ढुलमुल, आर्थिक व चारित्रिक रूप से भ्रष्ट तत्वों को सरेंडर करवाना और पार्टी के खिलाफ में दुष्प्रचार चलाना, झूठी अफवाह फैलाकर मनोवैज्ञानिक दबाव डालना आदि। अलावे झूठा सुधार कार्यक्रम व रिलिफ-राहत का कार्यक्रम चलाना।

आज दुश्मन ने सैनिक हमले से जितना नुकसान हमें नहीं पहुंचाया है उससे अधिक पार्टी के आन्तरिक हमले से नुकसान पहुंचाया है। इसका मूल कारण है हमारे पूरे पार्टी

कतारों और पीएलजीए के फारमेशनों के अन्दर राजनीतिक व सैद्धांतिक मामले में कमी-कमजोरी रहना। हमारी राजनीतिक व सैद्धांतिक कमजोरी के कारण ही हम अपने आपको वर्गच्यूत कर सर्वहारा वर्ग व एक कम्युनिस्ट के रूप में बदल नहीं पाते हैं। जिसके कारण हमारे अन्दर आंशिक तौर पर पहले से मौजूद निम्नपूंजीवादी व गैर-सर्वहारा रूझान बढ़ जाता है और हमारे विकास के सामने बाधक बन जाता है और हमें अध:पतन की ओर ले जाता है। इसलिए पार्टी और पीएलजीए को राजनीतिक और सैद्धांतिक रूप से मजबूत करने के लिए बोल्शेवीकरण का जो अभियान चलाया जा रहा है उसकी समीक्षा करते हुए लगातार चलाना होगा।

आज क्रांतिकारी आन्दोलन से जो पीछे हट रहे हैं, पार्टी के साथ गद्दारी करके दुश्मन के समक्ष आत्मसमर्पण कर रहे हैं या भीतरघाती कर रहे हैं, उनके अन्दर गैर-सर्वहारा रूझान मौजूद रहता है और उससे ग्रस्त होता है। इसी कारण वे पार्टी, क्रांति और सामूहिक हित को प्रधानता न देकर अपने व्यक्तिगत हित को प्रधानता देते हैं और व्यक्तिगत स्वार्थ, लोभ-लालच, ऐशो-आराम की प्रवृति उनके अन्दर में पनपने लगता है, जिससे वे त्याग, कठिनाई, कष्ट, दुख-तकलीफ झेलने और आत्मत्याग करने से हिचकिचाते हैं। वैसे ही लोग दुश्मन के गुलामी की जिन्दगी स्वीकार कर दुश्मन के समक्ष आत्मसमर्पण कर देते हैं। उनके अन्दर राजनीतिक समझदारी व इज्जत-अधिकार बोध रहेगा, सर्वहारा वर्ग दृष्टिकोण रहेगा साथ ही साथ स्वार्थी नहीं होगा तो वे कभी भी दुश्मन के सामने आत्मसमर्पण नहीं कर सकते हैं।

हमें पार्टी व क्रांति के साथ गद्दारी करनेवालों, दुश्मन के पास आत्मसमर्पण करने वालों के प्रति घृणा करना चाहिए। ऐसे लोगों का नाम काला खाता में लिखकर रखना चाहिए और जब भी मौका मिले जनअदालत में पेश कर उसका राजनीतिक भण्डाफोड़ किया जाना चाहिए तथा 'जैसा कुत्ता वैसा डण्डा की सजा' दी जानी चाहिए। उसको क्रांतिकारी पांतों के साथ-साथ गांव समाज से भी बहिष्कार कर देना चाहिए।

हमें समझना होगा कि वर्ग दुश्मन का भविष्य अन्धकारमय है, उसका विकास अवरूद्ध है और हमारा भविष्य उज्जवल है, हमारा विकास उर्द्धगामी है। दुश्मन की शक्ति अभी हमसे ज्यादा है, लेकिन सीमित है। हमारी शक्ति अभी दुश्मन से कम है लेकिन असीमित है, दुश्मन की शक्ति घटेगी और हमारी शक्ति बढ़ेगी। अभी आत्मगत रूप से कमजोर होने के कारण दुश्मन हावी है। लेकिन यह स्थिति स्थायी नहीं अस्थायी है। अतएव हमें धैर्य और साहस के साथ दुश्मन के हमले का मुकाबला करते हुए व्यापक जनता को जनयुद्ध में शामिल करना होगा। जनता को हम जितना ही जनयुद्ध में शामिल कर पाएंगे उतना ही दुश्मन के हमले का मुकाबला करने में हम सक्षम होंगे और दुश्मन के बर्बर युद्ध अभियान ऑपरेशन ग्रीन हंट को परास्त कर क्रांतिकारी आन्दोलन को और एक कदम आगे बढ़ाने में अवश्य सक्षम होंगे। बशर्ते कि हम छापामार युद्ध के नियम को सृजनात्मक रूप से लागू करें।

शोषक-शासक वर्ग द्वारा मेहनतकश वर्ग के खिलाफ छेड़े गये बर्बर युद्ध अभियान ऑपरेशन ग्रीन हंट को परास्त करें तथा भाकपा (माओवादी) के नेतृत्व में गांव-गांव, इलाके-इलाके में वैकल्पिक जनसत्ता व जनसरकार के निर्माण हेतु जारी जनयुद्ध को तेज करने का आह्वान

प्रिय मेहनतकश अवाम, यह जग जाहिर है कि आज शोषक-शासक वर्ग माओवादी आन्दोलन को दमन करने के नाम पर अघोषित रूप से ऑपरेशन ग्रीन हंट नामक बर्बर युद्ध अभियान जनता पर थोप दिया है। जिसके तहत न केवल माओवादी क्रांतिकारियों के ऊपर बर्बर हमले चला रहे हैं, बल्कि शोषक-शासक वर्ग के लूट-शोषण के खिलाफ तथा अपनी किसी भी जायज मांगों को लेकर किसान-मजदूर व मेहनतकश जनता आवाज उठाते हैं तो उन्हें भी नहीं बख्शा जा रहा है। माओवादी व आतंकवादी करार देकर उसके ऊपर बर्बर हमले किये जा रहे हैं। न्यूनतम जनवादी अधिकारों को भी बूटों तले रौंदा जा रहा है। एक साजिश के तहत जल-जंगल-जमीन को आदिवासी-मूलवासियों से छीन कर पूंजीपतियों व कॉरपोरेट घरानों को सौंपा जा रहा है। जोर-जबरन कृषि भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है। इसका विरोध करने पर पुलिस की गोली का निशाना बनाया जा रहा है। गोरक्षा के नाम पर अल्पसंख्यकों व दलितों के ऊपर कातिलाना हमले किये जा रहे हैं व हत्याएं की जा रही हैं। राष्ट्रीयसत्ता के आन्दोलनकारियों के ऊपर बर्बर दमन चलाया जा रहा है। इस तरह यह बर्बर दमन अभियान मेहनतकश जनता के ऊपर थोपा गया युद्ध के सिवा और कुछ नहीं हो सकता।

अतः भाकपा (माओवादी) के पूर्वी रीजनल ब्यूरो मजदूर-किसान, छात्र-नौजवानों, मेहनतकश महिलाओं, प्रगतिशील बुद्धिजीवियों सहित तमाम मेहनतकश जनता से आह्वान करता है कि आवें, साम्राज्यवाद-सामंतवाद और दलाल नौकरशाह पूंजीपति वर्ग के लूट-शोषण से मुक्ति पाने तथा सही इज्जत-आजादी व आर्थिक-राजनीतिक अधिकार हासिल करने हेतु भाकपा (माओवादी) के नेतृत्व में जारी जनयुद्ध या क्रांतिकारी आन्दोलन में कूद पड़ें तथा शोषक-शासक वर्ग द्वारा थोपे गये बर्बर युद्ध अभियान ऑपरेशन ग्रीन हंट के खिलाफ जनयुद्ध को तेज कर उसे परास्त करें तथा ग्रामीण क्षेत्र से शोषक-शासक वर्ग के शोषण सत्ता को उखाड़ फेंक कर जनता की जनसत्ता व जन सरकार के बतौर गांव-गांव, इलाके-इलाके में क्रांतिकारी जन कमिटी का निर्माण करें। आवें, 28 जुलाई से 3 अगस्त 2017 तक मनाये जा रहे पार्टी शहीदी सप्ताह को सफल करने हेतु इस अवसर पर आयोजित जुलूस व आमसभा में व्यापक पैमाने पर शामिल हों।

क्रांतिकारी अभिवादन के साथ

पूर्वी रीजनल ब्यूरो

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)

11 जुलाई, 2017